



उज्ज्वल भारत



वर्ष

**उपलब्धियां और
पहल**

विद्युत, कोयला, नवीन और
नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान मंत्रालय,
भारत सरकार

मई 2017



न्यू इण्डिया की ओर



मिशन

24x7

सभी के लिए

सस्ती स्वच्छ बिजली

हर चेहरे पर

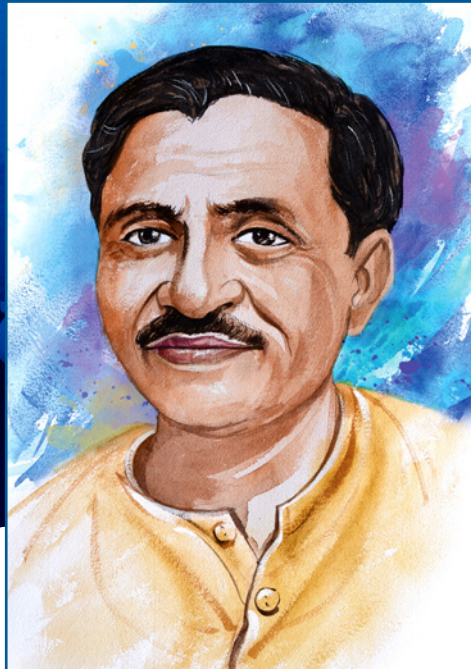
मुस्कुराहट

- 😊 19 मई, 2017 तक 18,452 में से 13,511 गाँवों में बिजली पहुँचाई गई
- 😊 पहला ऐसा वर्ष जब विद्युत की अधिकता रही और कोयले की कोई कमी नहीं रही
- 😊 वर्ल्ड बैंक के बिजली प्राप्त करने की सहूलियत सूचकांक पर भारत का क्रम जो 2015 में 99 था, उठकर 2017 में 26वें स्थान पर आया
- 😊 कोल इंडिया के द्वारा 2013-14 के 46.2 करोड़ टन के मुकाबले 2016-17 में 55.4 करोड़ टन कोयले का उत्पादन
2013-14 से पहले 9.2 करोड़ टन की इस वृद्धि को हासिल करने में लगभग 7 साल लगे थे, यह उपलब्धि अब सिर्फ 3 साल में हासिल की गई
- 😊 प्रति यूनिट बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले की मात्रा में पिछले 3 साल में 8% तक की कमी
- 😊 2016-17 में पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा की शुद्ध बढ़त, पारंपरिक ऊर्जा की शुद्ध बढ़त से ज्यादा
- 😊 सौर और पवन ऊर्जा अब तक के सबसे कम मूल्य पर उपलब्ध
- 😊 2011-12 की तुलना में 2016-17 में पावर एक्सचेंज से खरीदी गई शॉर्ट टर्म पावर के मूल्य में औसतन एक तिहाई गिरावट
- 😊 उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन क्षमता में अब तक की सर्वाधिक बढ़ोत्तरी
- 😊 लगभग ₹ 2.32 लाख करोड़ मूल्य के UDAY बांड जारी किए गए जिससे ब्याज में ₹ 12,000 करोड़ की बचत
- 😊 56 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए। उजाला (UJALA) के अंतर्गत सरकार द्वारा 23 करोड़ और निजी क्षेत्र द्वारा 33 करोड़
- 😊 ₹ 1.1 लाख करोड़ अनुमानित मूल्य से अधिक के संसाधनयुक्त 24 खनिज ब्लॉक की पारदर्शी रूप से नीलामी की गई
- 😊 पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक सुविधा के लिए नए मोबाइल एप्स लॉन्च किए गए। 18002003004 पर मिस्ड कॉल देकर डाउनलोड कर सकते हैं

अंत्योदय

छोर पर खड़े आखिरी व्यक्ति की सेवा

पंडित दीन दयाल
उपाध्याय से प्रेरित



पंडित दीन दयाल उपाध्याय
के जन्म शताब्दी वर्ष को
'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप
में मनाते हुए

“ 125 करोड़ भारतवासियों की 'टीम इण्डिया' की अब ये पवित्र प्रतिज्ञा है कि इन 18,500 गाँवों में बिजली के खंभे, तार और बिजली पहुँचाने का लक्ष्य अगले 1,000 दिनों में हासिल कर लिया जाएगा ”

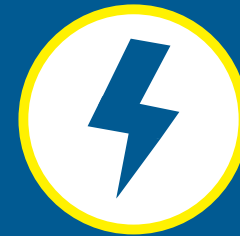
- 15 अगस्त 2015

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी

सभी मज़रों और घरों में बिजली सुनिश्चित करना



राज्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 19 मई, 2017 तक दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अंतर्गत 18,452 (1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार) में से **13,511** गाँवों में बिजली पहुंचाई गई



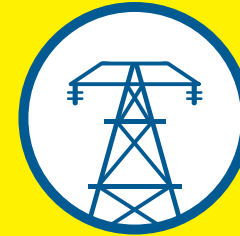
गरीब से गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गाँवों में बिजली पहुंचाने की रफ्तार में पर्याप्त वृद्धि हुई

- 2013–14 के दौरान 9.6 लाख के मुकाबले 2016–17 में बीपीएल परिवारों को 22.4 लाख मुफ्त कनेक्शन



ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मात्रा और गुणवत्ता की निगरानी

- ग्रामीण फीडर निगरानी योजना में सभी 1 लाख ग्रामीण और कृषि फीडर शामिल हैं



4.2 गुना वृद्धि

2013–14 के 14,956 गाँवों की तुलना में 2016–17 में **63,330** गाँवों में सघन विद्युतीकरण का कार्य

DDUGJY के द्वारा सभी के लिए 24x7 सस्ती, विश्वसनीय और पर्याप्त बिजली

- ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता देते हुए लगभग ₹ 76,000 करोड़ का आवंटन
- सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के तहत सभी गांवों की व्यापक कवरेज
- ग्रामीण वितरण के ढांचे को मजबूत करने के लिए नयी योजना
- गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार के लिए निःशुल्क कनेक्शन
- सब-ट्रांसमिशन और वितरण ढांचे में सुदृढ़ता और वृद्धि
- माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण तंत्र
- कृषि एवं गैर कृषि फीडरों को अलग-अलग करना
- फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों और उपभोक्ताओं के लिए मीटर

गाँव से घर तक

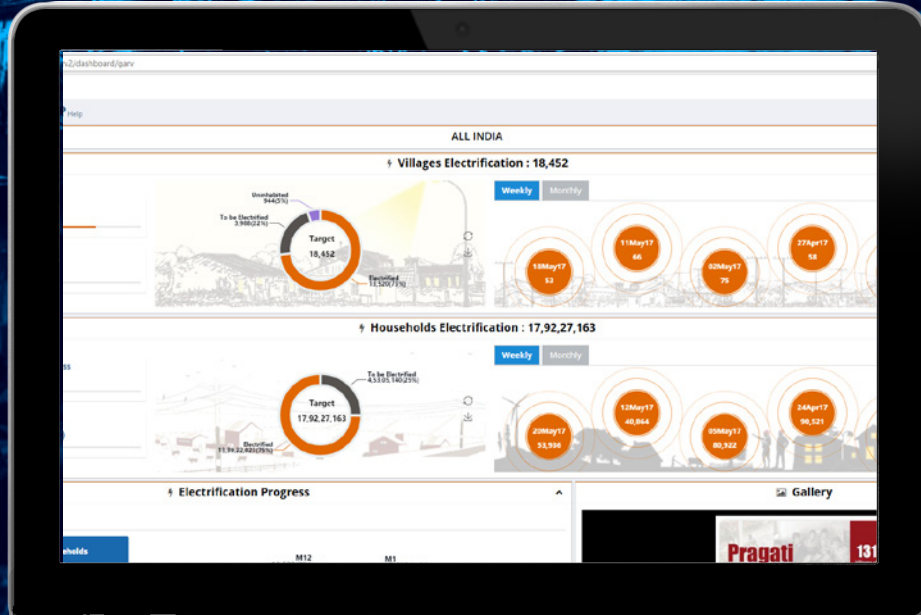


लोगों के घरों में बिजली पहुँचाने की व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ऐप

6,00,000 गाँव
17.92 करोड़ घर

शामिल
किए गए

ड्रिल डाउन नक्शों में गाँव और घरों में बिजली पहुँचाने की स्थिति का जिले-वार विवरण दिया गया है
शेष बचे 4.53 करोड़ ग्रामीण घरों तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य



ग्राम विद्युत अभियंताओं (GVA) के माध्यम से बुनियादी स्तर पर कार्यान्वयन

www.garv.gov.in
से प्रगति पर नजर रखें



बिजली

एक बेहतर भविष्य के लिए



दामपुरा गाँव राजस्थान

जब GVA ने राजस्थान के दामपुरा गाँव के निवासियों को बताया कि उनके गाँव में बहुत जल्दी बिजली आ जाएगी तो उनका जवाब था, "अब तक, हम लोग ही सरकारी अधिकारियों के पास जाते थे। लेकिन आज, जब आप हमारे पास आए हैं तो हमें लगता है कि हमारी जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है, और हमारे गाँव में जल्द ही बिजली आ जाएगी।" गांववाले खुश थे, वे मुस्कुरा रहे थे और उनकी आँखों में खुशी के आंसू थे। एक बूढ़ी महिला ने खुश होकर आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, "धन्यवाद, मोदी जी का, हमारी सेवा करने के लिए। उन्होंने मेरे गाँव में उजाला कर दिया है"



खजुहान गाँव बिहार

बिहार के खजुहान गाँव के एक उद्यमी और जिम्मेदार नौजवान, सचिदानंद को जैसे ही पता चला कि उसका गाँव, सरकार के 18,452 गाँवों में बिजली पहुंचाने के मिशन का हिस्सा है, उसने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी निष्ठापूर्वक ट्रैकिंग की। उसे अपने ट्वीट के लगातार जवाब मिलते रहे जिससे उसे काफी प्रोत्साहन मिला



जिस दिन गाँव को बिजली मिली, उस दिन उस गाँव के लोगों के चेहरों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। गाँव में त्यौहार का माहौल बन गया, चारों तरफ मिठाइयाँ बाँटी जाने लगी, और लोगों ने उन्हें सशक्त और उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ की

बिजली की कमी से बिजली की प्रचुरता तक



पारंपरिक बिजली में लगभग 60
गीगावाट क्षमता की बढ़ोत्तरी

- 3 साल की अवधि की अब तक की सबसे अधिक क्षमता
- मार्च, 2014 तक स्थापित की गई क्षमता में एक-चौथाई से भी ज्यादा की वृद्धि

समझौता ज्ञापन पर उत्तर प्रदेश के हस्ताक्षर
के साथ सभी राज्य 'सभी के लिए 24x7
बिजली' अभियान में शामिल

- सबको 24x7 बिजली देने के उद्देश्य से भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक संयुक्त पहल

मेगा पॉवर पॉलिसी

- भावी पॉवर परचेज एग्रीमेंट्स (PPA) के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की सुविधा प्रदान करती है
- दीर्घकालिक परियोजना व्यवहार्यता को सुनिश्चित करती है
- बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती है

पहली बार बिजली का निर्यात,
आयात से ज्यादा

- 2016-17 में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में निर्यात किया

टैरिफ पॉलिसी 2016 को संशोधित किया गया, ताकि निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित हों

- सबको बिजली मिले
- दक्षता के द्वारा सस्ती बिजली
- धारणीय भविष्य के लिए पर्यावरण
- व्यापार करने में सहूलियत

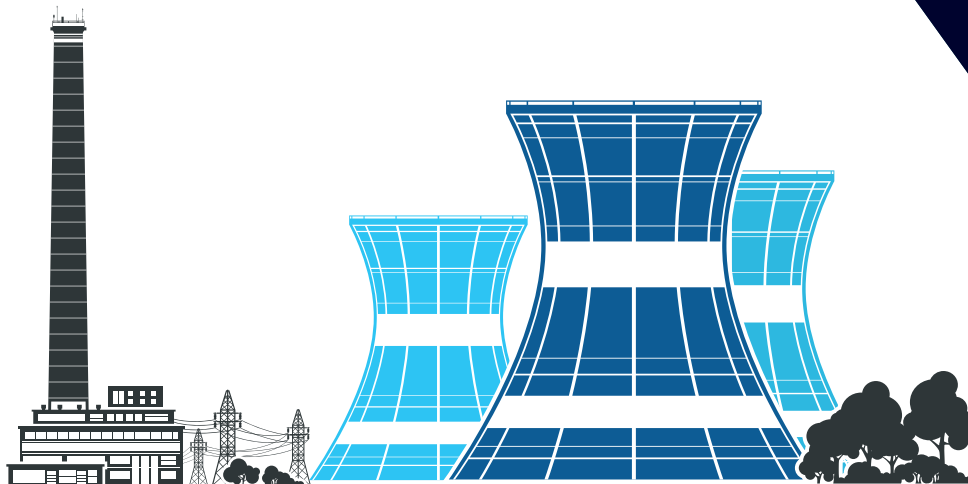
जल विद्युत ऊर्जा का दोहन करने के लिए
नई नीति बनाई जा रही है

शक्ति (SHAKTI)

(भारत में पारदर्शी रूप से कोयला
दोहन और आवंटन की स्कीम)

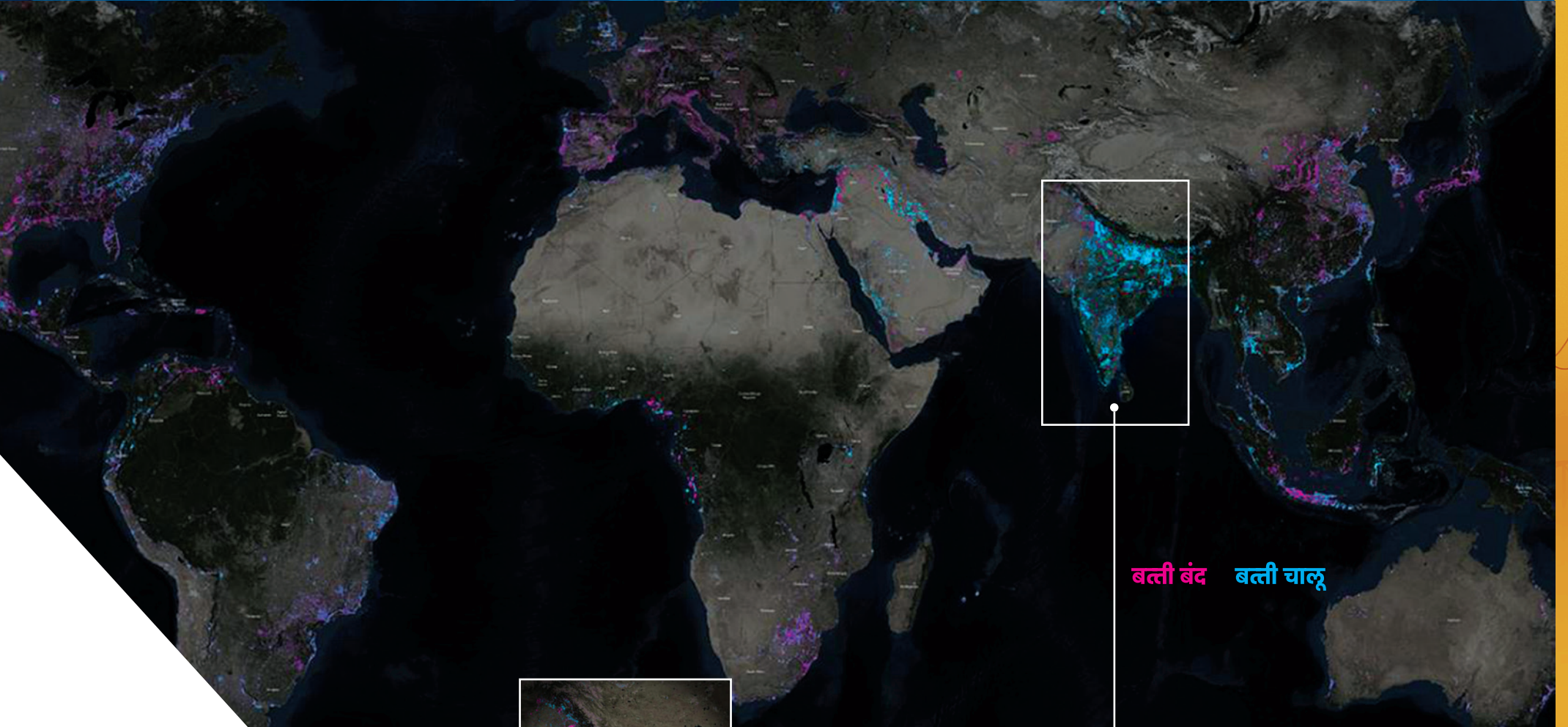
कोयला लिंकेजेस की नीलामी और आवंटन के लिए
सुधारात्मक योजना से यह सुनिश्चित होगा :

- सस्ती बिजली
- कोयले की उपलब्धता
- कोयले के आवंटन में पारदर्शिता

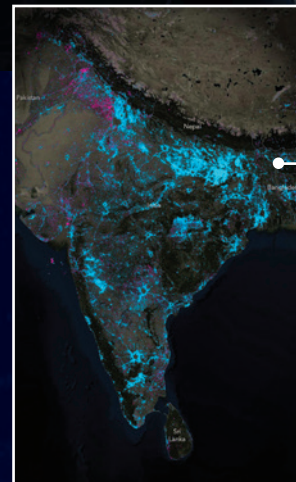


उज्ज्वल भारत बेहतर भारत

नासा द्वारा हाल ही में जारी किया गया रात के समय का नक्शा भारत को बिल्कुल नई रोशनी में दिखाता है (2012 के मुकाबले 2016)



बत्ती बंद बत्ती चालू



“भारत अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल हुआ है, यह आश्चर्य नहीं है। इस देश में बिना बिजली के भारी संख्या में लोग रहते हैं और उनकी सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को स्थापित करके एवं नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश करके इस स्थिति को बदलने के लिए काम कर रही है”

— नेशनल ज्योग्राफिक

स्रोत: एनएसए: बेट्सी मैसन एंड जॉन नेल्सन
नेशनल ज्योग्राफिक, दिनांक 29 अप्रैल 2017

ट्रांसमिशन में आधारभूत परिवर्तन

एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक मूल्य

ट्रांसमिशन नेटवर्क में तेजी से विस्तार

मार्च, 2014 के 5.3 लाख एमवीए से बढ़कर मार्च 2017 में 7.4 लाख एमवीए होने से ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में लगभग 40% की वृद्धि

मार्च, 2014 के 2.9 लाख सर्किट कि.मी. से बढ़कर मार्च 2017 में 3.7 लाख सर्किट कि.मी. होने से ट्रांसमिशन लाइनों में एक-चौथाई से भी अधिक वृद्धि

मार्च, 2014 से दक्षिण भारत में उपलब्ध अंतरण क्षमता (अवेलेबल ट्रांसफर कैपेसिटी) में 116% वृद्धि

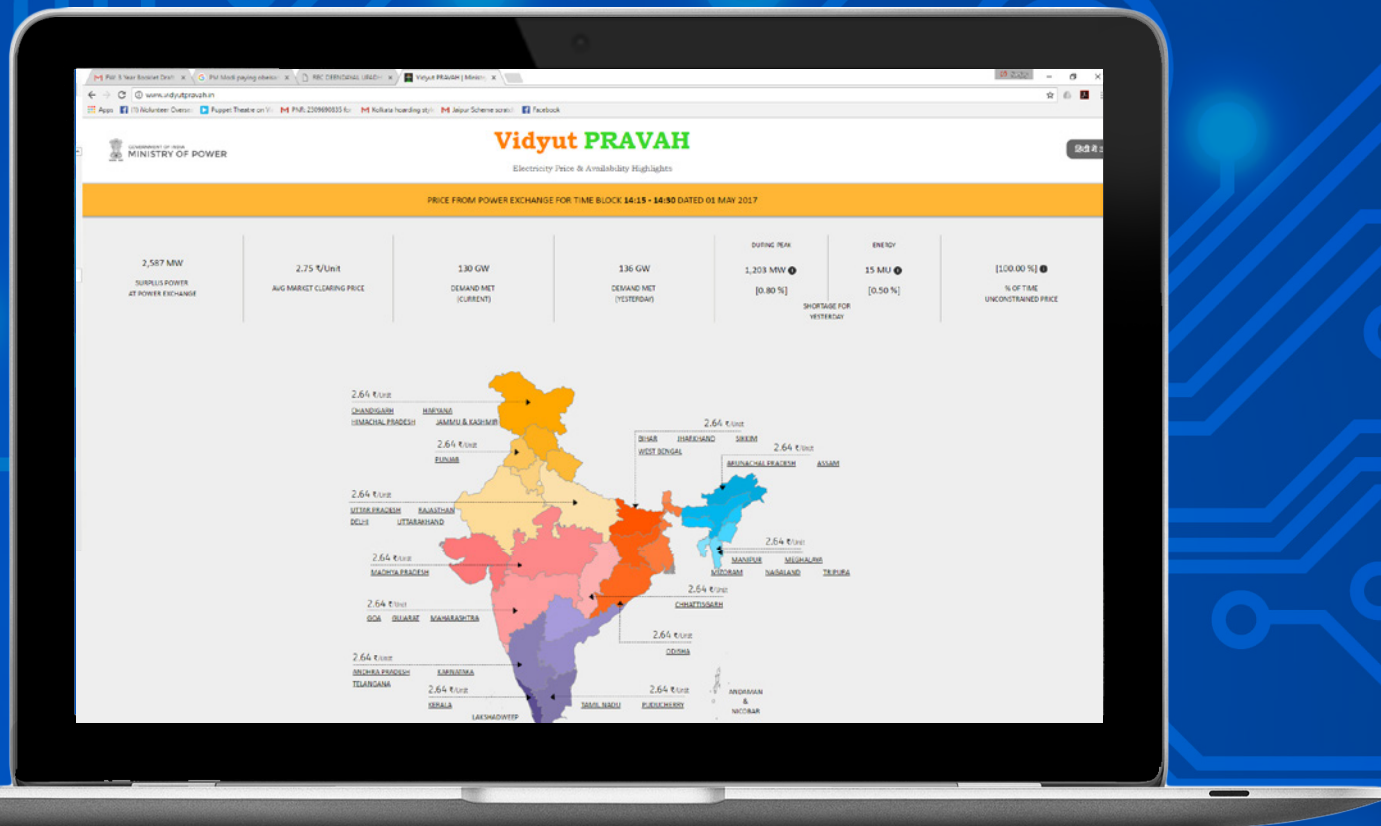
2019 तक क्षमता को तीन गुना बढ़ाकर 18,400 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य
ट्रांसमिशन बाधाओं के दूर होने से बिजली की कमी की समस्या घटी

2014–17 के दौरान ₹1.5 लाख करोड़ मूल्य की परियोजनाएं चालू की गईं

2011–14 की तुलना में 83% अधिक परियोजनाएं चालू की गईं

स्थायी और सुरक्षित ग्रिड

मई, 2014 से ग्रिड में कोई भी बड़ा अवरोध नहीं आया है



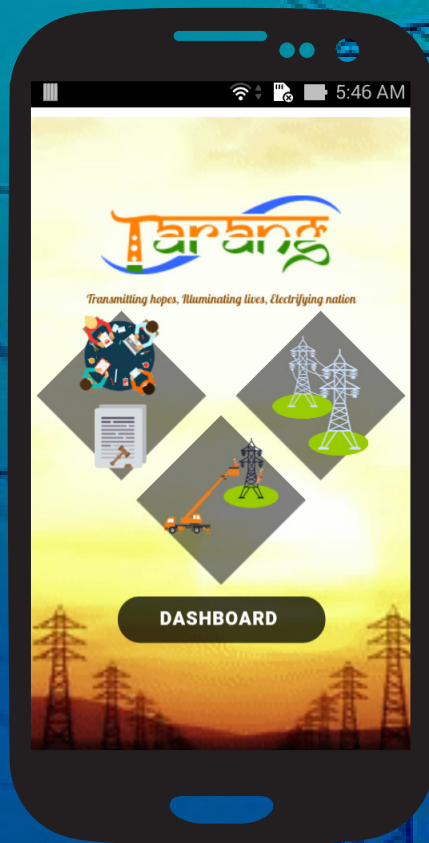
विद्युत प्रवाह उपभोक्ता ही सर्वोपरि है

बिजली की कीमत और बिजली की उपलब्धता पर रियल टाइम जानकारी कम दरों पर अधिशेष बिजली उपलब्ध है, जिसे कोई भी राज्य एक्सचेंज से खरीद सकता है



www.vidyutpravah.in

ट्रांसमिशन में पारदर्शिता



तरंग (TARANG)

(रियल टाइम निगरानी और वृद्धि के लिये मोबाइल ऐप)

आगामी ट्रांसमिशन परियोजनाओं और अंतर्राज्यीय एवं अंतरा-राज्य ट्रांसमिशन प्रणालियों की प्रगति पर नजर रखता है



www.tarang.website

सर्वोत्तम मूल्यों का पता लगाने के लिए ट्रांसमिशन परियोजनाओं में ई-बिडिंग और ई-रिवर्स (e-reverse) नीलामियों के लिए ई-ट्रांस (e-trans)

दीप DEEP

(बिजली की उचित कीमतों का पता लगाना)



यह सुनिश्चित करना कि शॉर्ट टर्म व मीडियम टर्म की पॉवर खरीद के लिये पारदर्शी ई.बिडिंग तथा ई.रिवर्स नीलामी की व्यवस्था ताकि डिस्कॉम को सर्वोत्तम कीमत मिले

वितरण क्षेत्र के लिए एक नया सवेरा

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY)
ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक व्यापक सुधार है

डिस्कॉम की विगत, वर्तमान और भावी समस्याओं का
स्थायी समाधान

वित्तीय और प्रचालन दक्षता सुधारों
के माध्यम से डिस्कॉम में भारी बदलाव

27 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, जिनके डिस्कॉम का कुल कर्ज में **97%**
हिस्सा है, उदय से जुड़े हैं

उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बिजली
कम ब्याज दर के कारण डिस्कॉम की लगभग ₹ 12,000 करोड़ की बचत

वितरण क्षेत्र में विशाल अवसर
• भावी निवेश के लिए तैयार • रोजगार सृजन की व्यापक संभावना

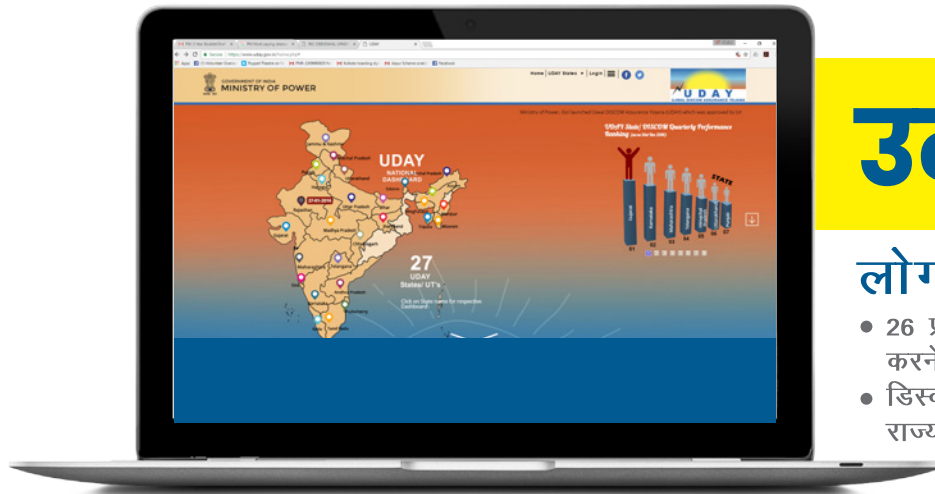
राज्य राह दिखाते हैं

हरियाणा की "म्हारा गाँव जगमग गाँव" स्कीम

- गाँव वालों की नुकसान कम करने की प्रतिबद्धता के बदले में ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति
- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने 2014 के अपने लगभग ₹ 2,088 करोड़ से अधिक के नुकसान को 2016-17 की प्रथम छमाही में ₹ 78 करोड़ के लाम में बदल दिया

राजस्थान का "मुख्य मंत्री विद्युत सुधार अभियान"

- विभिन्न तकनीकी और चोरी रोकने के उपायों के माध्यम से नुकसान को कम कर रहा है
- 100% फीडर्स पर मीटर लगाया गया
- बिजली की चोरी रोकने के लिए स्वयं-सहायता महिला समूहों का गठन किया गया



उदय UDAY मोबाइल ऐप और पोर्टल

लोगों को सुविधा देता है

- 26 प्रमुख पैरामीटरों के आधार पर डिस्कॉम की तुलना करने की
- डिस्कॉम की वित्तीय और प्रचालन स्थिति के आधार पर राज्यों की रैंकिंग को देखने की



www.uday.gov.in

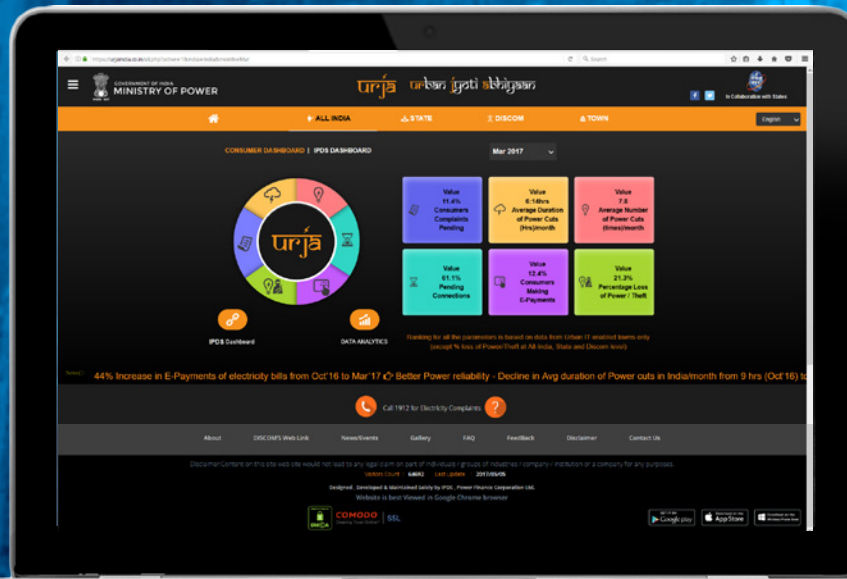
स्मार्ट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर

शहरी घरों में 24x7 घंटे अच्छी गुणवत्ता की और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति के लिए इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (IPDS)



₹ 65,000

करोड़ रुपए से अधिक का परिव्यय



www.urjaindia.co.in

उपभोक्ता, शहरों में बिजली की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं

इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (IPDS) की प्रगति को दिखाता है

ऊर्जा URJA अर्बन ज्योति अभियान

ऊर्जा मित्र

सूचना से शक्ति



एसएमएस और ई-मेल के जरिए, बिजली की कटौती से पहले इसकी सूचना 9 करोड़ उपभोक्ताओं को भेजी गई बिजली कटौती के पिछले डाटा की जाँच और तुलना की जा सकती है

लोग पहली बार सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबर **1912** के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं, डिस्कॉमों की जवाबदेही बढ़ी

सम्मिलित : 25 राज्यों एवं संघ राज्य – क्षेत्रों के 44 डिस्कॉम



www.urjamitra.com

प्रकाश पथ



उजाला (उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल)

विश्व का सबसे बड़ा एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम

उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में लगभग ₹ 12,000 करोड़ की बचत



ऊर्जा क्षमता

2014-17 के बीच डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) ऊर्जा उत्पादन की सालाना वृद्धि को 8.61 प्रतिशत से कम करके 5.74 प्रतिशत पर ले आया



7 लाख से अधिक ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए गए

जो उपभोक्ता के बिजली के बिल में प्रति वर्ष ₹ 400-500 की कमी ला सकते हैं



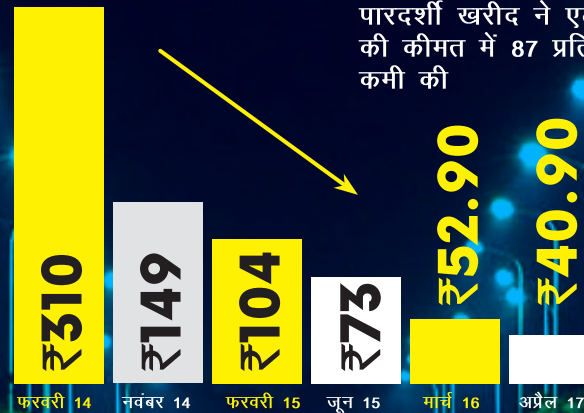
18.5 लाख से अधिक एलईडी ट्यूबलाइट वितरित की गईं

400-600 रुपये की फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की तुलना में कीमत ₹ 230



एसएलएनपी (SLNP-स्ट्रीटलाइट नेशनल प्रोग्राम) के तहत 20 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं

पारदर्शी खरीद ने एलईडी बल्बों की कीमत में 87 प्रतिशत की कमी की



एलईडी बल्ब्स की वॉट क्षमता 7 वॉट से बढ़कर 9 वॉट हुई



उजाला योजना की प्रगति को ट्रैक करना

कार्यक्रम के बारे में उजाला डैश बोर्ड रियल टाईम अपडेट प्रदान करता है



www.ujala.gov.in

कोयले

कमी से प्रचुरता तक

2014 में प्रमुख पावर प्लांट्स में से दो-तिहाई प्लांट्स के पास कोयले की अत्यधिक कमी हो गई थी और उनके पास 7 दिनों से भी कम का स्टॉक बचा था, आज कोयले की कोई कमी नहीं है

कोयले के 84 ब्लॉक्स की पारदर्शी ई-नीलामी और आवंटन

- खानों के जीवनकाल के दौरान कोयलाधारक राज्यों के लिए ₹ 3.94 लाख करोड़ रुपए की संभावित आय

कोयले की चोरी को रोकने के लिए आईटी-आधारित पहल

अन्वेषण के लिए ड्रिलिंग में 62 प्रतिशत की वृद्धि

- 2013-14 के 6.9 लाख मीटर से 2016-17 में 11.3 लाख मीटर

कोयले के आयात में कमी

- ₹ 25,900 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा बचाई गई



प्रचुरता से श्रेष्ठता

बिजली सस्ती करना:

- पिछले 3 वर्षों में प्रति यूनिट बिजली बनाने में जितने कोयले की मात्रा लगती थी (कोयले की विशिष्ट खपत) उसमें 9 प्रतिशत की कमी आई
- कोयले की गुणवत्ता और आपूर्ति के साथ-साथ बिजली उत्पादन में सुधारों के कारण यह उपलब्धि हुई
- 2016-17 में 1 यूनिट बिजली पैदा करने के लिए 0.63 किलो कोयले का उपयोग हुआ जबकि 2013-2014 में 0.69 किलो कोयला लगता था

कोयले की गुणवत्ता में सुधार

- 41.9 करोड़ टन की तृतीय पक्ष द्वारा जांच शुरू हुई
- अब पावर प्लांट्स पर 100 प्रतिशत क्रशड (चूरा) कोयला जाता है

कोल मित्र पोर्टल

- घरेलू कोयले के उपयोग में सहूलियत लाने लिए शुरू किया गया
- उपभोक्ताओं के लिए बिजली का कम दाम

लगभग 4 करोड़ टन के कोयला लिंकेज का रेशनलाइजेशन

- लगभग ₹ 3,000 करोड़ की संभावित बचत



स्वच्छ ऊर्जा

विश्व की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना



“ मेरे लिए नवीकरणीय ऊर्जा आस्था का विषय है। हम भविष्य के अधिक हरित विश्व के लिए आज हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहे हैं ”

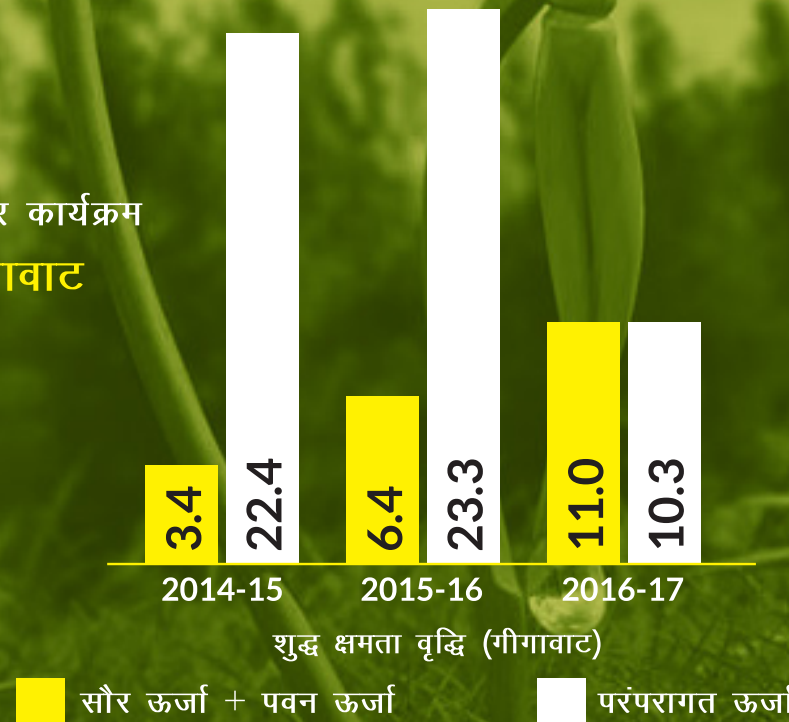
— माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

ऐसा पहली बार हुआ है कि नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में शुद्ध वृद्धि परंपरागत ऊर्जा की क्षमता में शुद्ध वृद्धि से अधिक हो गई

विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम

2022 तक 175 गीगावाट

2016-17 में नवीकरणीय ऊर्जा में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़त



परिवर्तन की बयार

चौथी

सबसे बड़ी

विश्व में पवन ऊर्जा क्षमता

- 2016–2017 में 5.5 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि
- संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में 52% की वृद्धि – मार्च, 2014 के 21 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2017 में 32 गीगावाट से अधिक

प्रति यूनिट

₹ 3.46

का रिकार्ड पवन टैरिफ

17%

स्थिर दरों की बजाय प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के कारण पवन ऊर्जा लागत में कमी

निम्नलिखित के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति

ग्रिड से जुड़ी हुई बड़ी पवन-सौर पीवी प्रणाली को बढ़ावा देना

ग्रिड की बेहतर स्थिरता

ट्रांसमिशन के बुनियादी ढाँचे का सर्वोत्तम उपयोग

पिछले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा में **370 प्रतिशत की वृद्धि हुई**। पहले के लगभग 2.6 गीगावाट की तुलना में अब 12.2 गीगावाट से अधिक हो गई है



बाढला, राजस्थान में ₹ 2.44/यूनिट का **रिकार्ड न्यूनतम सोलर टैरिफ** प्राप्त किया गया



सौर ऊर्जा में जगतगुरु
इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने भारत को जगतगुरु की पदवी दी है
इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क करार पर 25 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं
अन्य 96 भावी सदस्य देश इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं



1991–2014 की तुलना में 2014–17 के बीच लगभग 9 गुना अधिक सोलर पंप लगाये गये
मार्च 2014 तक के 11,600 पंपों की तुलना में 1.1 लाख सोलर पंप संस्थापित किए गए हैं



बिजली के न होने पर विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए इसलिए उनमें **10 लाख सोलर लैम्प** वितरित किए गए।
अन्य 70 लाख ग्रामीण विद्यार्थियों को सोलर लैम्प मुहैया कराए जाएंगे



संग्राहक क्षेत्रों में कंसंट्रेटिड सोलर थर्मल (सीएसटी) में **130 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई**, 2014 में यह 23,000 वर्ग मीटर था जो अब बढ़कर 53,000 वर्ग मीटर हो गया है



सोलर रूफटॉप

स्थापित क्षमता में 15 गुना वृद्धि हुई, 2014-15 में यह 41 मेगावाट थी जो कि 2016-17 में बढ़कर 656 मेगावाट हो गई



विश्व का सबसे बड़ा भूमि पर स्थापित सौर संयंत्र और विश्व का सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप दोनों ही भारत में हैं



सोलर पार्क

प्लग एंड प्ले मॉडल का उपयोग करके सौर ऊर्जा टैरिफ में 75 प्रतिशत से अधिक की कमी आई, सोलर पार्क स्कीम 20 गीगावाट से दोगुनी करके 40 गीगावाट की गई



एनटीपीसी लिमिटेड और सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआर) द्वारा ऑफटेक रिस्क लेकर तथा नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए डेडिकेटेड ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा सौर ऊर्जा विकास को आकर्षक बनाया गया

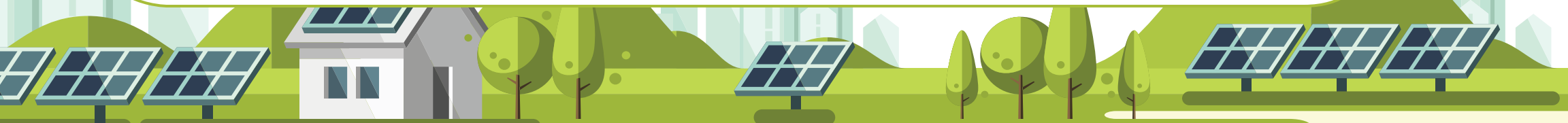


प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने और जोखिमों में कमी लाने के लिए बोली के नए दिशा-निर्देश तैयार किए गए



उपभोक्ता की सुविधा के लिए मोबाइल एप्स

सूर्य मित्र – ग्राहक के घर पर सोलर रूफ टॉप प्रणालियों की संस्थापना, सर्विस तथा मरम्मत
ARUN (अटल रूफटॉप सोलर यूजर नेवीगेटर) – सोलर रूफ टॉप प्रणालियों की स्थापना में सहायता के लिए



राष्ट्रीय विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

अन्वेषण को बढ़ावा देना

अन्वेषण को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय
खनिज अन्वेषण नीति 2016

राष्ट्रीय एयरो-जियोफिजिकल मैपिंग प्रोजेक्ट

- गहराई में पाए जाने वाले खनिजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए
- पिछले 30 वर्षों के केवल 7 लाख लाइन किलोमीटर के मुकाबले 2019 तक 27 लाख लाइन किलोमीटर एयरो-जियोफिजिकल डेटा हासिल करने का लक्ष्य

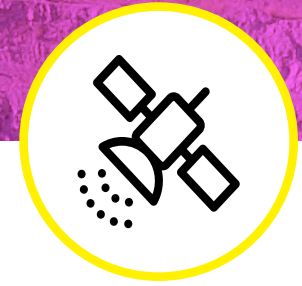




- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के द्वारा सभी के लिए बेस लाइन जियो-साइंस डेटा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है
 - 6,000 से अधिक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध हैं
- पिछले तीन वर्षों में एमईसीएल (खनिज अन्वेषण निगम लि.) ने अन्वेषण कर लगभग 900 करोड़ टन खनिज संसाधनों की मौजूदगी का पता लगाया है
- ऑफशोर ब्लॉकों के आवंटन के लिए विधायी ढाँचे में संशोधन करके ऑफशोर खनन गतिविधि की शुरुआत करना

पारदर्शिता

- पारदर्शी नीलामी
 - ₹ 1.1 लाख करोड़ से अधिक की अनुमानित आय संसाधनों के साथ 24 खनिज ब्लॉकों की मई 2017 तक नीलामी की गई
 - खानों की पट्टे की अवधि के दौरान राज्यों को ₹ 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अनुमानित राजस्व
 - मध्य प्रदेश में देश के अब तक के पहले हीरे के ब्लॉक की नीलामी हुई
- मोबाइल ऐप ताम्र (TAMRA - पारदर्शिता, नीलामी की निगरानी एवं संसाधन वृद्धि)
 - नीलाम किए जाने वाले/गए खनन ब्लॉकों की स्थिति की निगरानी की सुविधा देता है
 - वैधानिक मंजूरीयों का पता लगाकर एवं उसमें तेजी लाकर खनन ब्लॉकों का तेजी से प्रचालन



आधुनिक प्रौद्योगिकी

अवैध खनन रोकना

खनन निगरानी प्रणाली (MSS)

गैरकानूनी खनन पर रोक लगाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जरिए आकाश से निगरानी

296 ट्रिगर्स हुए, 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में खनन गतिविधि का पता चला, 15 प्रतिशत मामलों में अनधिकृत खनन पाया गया

डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप लॉच किया गया

गैरकानूनी खनन को रोकने के लिए उपग्रह से ली गई तस्वीरों का प्रयोग करते हुए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी

अन्वेषण से आवंटन और आवंटन से खनन तक सम्पूर्ण खनिज जीवनचक्र को स्वचालित बनाने के लिए आईटी आधारित माइनिंग टेनामेंट सिस्टम (एमटीएस)

जन एवं पर्यावरण हितैषी

खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों के कल्याण के लिए
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)

कल्याण गतिविधियों के लिए जिला खनिज फाउंडेशनों (डीएमएफ) के तहत 2016-17 में
खनन से लगभग ₹ 7,150 करोड़ एकत्र किए गए

12 खनिज बहुल राज्यों में से 11 को कवर किया जा चुका है

पर्यावरण हितैषी खनन

सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क (एसडीएफ) को क्रियान्वित करने के लिए खानों
की स्टार रेटिंग शुरू की गई

छोड़ी गई खानों का आकलन करने एवं उन्हें खनन से पहले वाली स्थिति में
लाने के लिए एंबडेड माइंस पहल की गई

“अपनी युवा शक्ति के सपनों का न्यू इंडिया आकार ले रहा है। ऐसा न्यू इंडिया आकार ले रहा है जो अपनी नारी शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करता है। गरीबों को अवसर देने वाला न्यू इंडिया आकार ले रहा है”

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी



www.ujwalbharat.gov.in

 @UjwalBharat